

Availability of clozapine drag

3108. SHRI CHBMANBHAI MKKTA:

SHRI SARADA MOHANTY:

SHRIMATI MIRA DAS:

SHRI ANANTRAY DEVSHAN-
KER DAVE:

Will the PRIME MINISTER be pleased to
Mate:

(a) whether Clozapine, a mental drug
developed by Swiss Pharmaceutical San-
doz, is available in India; if so, at what price
in the market;

(b) whether the equivalent of Clozapine
drug is manufactured in India; if so, at what
price;

(c) whether Government have compared it
with Thorazine and its side effects; and

(d) whether any survey is done of the
effects of various mental drugs?

THE MINISTER OF STATE IN THE
MINISTRY OF CHEMICALS AND FER-
TILIZERS (SHRI CHINTA MOHAN): (a)
Clozapine is neither manufactured nor
marketed in India.

(b) and (c) No, Sir.

(d) Government is not aware of any such
survey.

प्रीद्योगिकी उन्नयन

3109. डा. जिनेश कुमर जैन :

श्री कलाश नारायण सारंग :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की
कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 मई,
1992 के 'स्टेट्समैन' में ट्रेटकोला जी
अपप्रडेशन ए मस्ट शीर्षक से छाने समाचार
की ओर बिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में
प्रीद्योगिकी उन्नयन के लिए कोई उपाय
किये हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या
है ?

रसायन और उद्योग मंत्रालय में
राज्य मंत्री (श्री चिन्ता मोहन) : (क)
जी, हाँ ।

(ख) और (ग) प्रीद्योगिकी उन्नयन
एक सतत प्रक्रिया है और प्रीद्योगिकी
उन्नयन के उपायों पर सरकार सम्बन्ध-समय
पर ध्यान देती रही है । तकनीकी उन्नयन
को प्रोत्साहन देने के लिए रसायन और
दूर-रसायन विभाग और तकनीकी विकास
महानिदेशालय (डोजीटीडी) ने अलग-अलग
विषयों पर विभिन्न तकनीकी सलाहकार
ग्रुप गठित किए हैं ताकि विद्यमान प्रीद्यो-
गिकी का मूल्यांकन किया जा सके और
उन्नयन के उद्देश्य से अन्तराल का फता
लगाया जा सके जिससे इसे अग्र और प्रथम
उपयुक्त और समकालीन बनाया जा सके ।

विज्ञान और प्रीद्योगिकी पर सरकार
के व्यय में योजनागत विकास के वर्षों में
काफी वृद्धि हुई है जो पहली योजना
(1951-56) में 20 करोड़ रुपए से बढ़-
कर छठी योजना में यह 3678 करोड़
रुपए हो गया है । वर्तमान में 1200
इन्-हाउस अनुसंधान और विकास एकक
वैद्य मान्यता प्राप्त हैं जिनमें से 350
रसायन और सम्बद्ध उद्योगों से हैं ।

मान्यता प्राप्त अनुसंधान और विकास
एककों को वर्तमान में उपलब्ध प्रोत्साहनों
और समर्थन के उपायों में प्रायतः सुविधाएं
प्रायकर में राहत, तीव्रतर मूल्यहासि लाभ,
राष्ट्रीय पुरस्कार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों
में वित्तीय सहायता, प्रीद्योगिक लाइसेंसिंग
नीति, जहां नयी प्रक्रियाएं अन्तर्गस्त हों
प्रयुक्त औषधों के लिए मूल्य नियंत्रण
आदेश से छूट आदि शामिल हैं ।

जैव-प्रीद्योगिकी विभाग ने जैव-प्रीद्यो-
गिकी के क्षेत्र में प्रीद्योगिकी उन्नयन के
लिए 46.5 करोड़ रुपए के कुल बजट
परिव्यय से सात मुख्य परियोजनाएं
आरम्भ की हैं ।

प्रीद्योगिकी के आधुनिकीकरण और
उन्नयन को बढ़ावा देने के विशिष्ट उद्देश्य
से 1976 से तकनीकी विकास निधि योजना
भी लागू है ।